



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 चैत्र 1940 (श0)
(सं0 पटना 347) पटना, वृहस्पतिवार 19 अप्रील 2018

सं० 1/सी01-15/2017 गृ0आ0-3252
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

रंजन कुमार सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 17 अप्रील, 2018

विषय :- बिहार राज्य में आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु आर्थिक अपराध इकाई में अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई के एक गैर संवर्गीय पद के सृजन की स्वीकृति।

आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक-8752 दिनांक 01.12.2011 द्वारा पुलिस महानिदेशक, बिहार के सीधे नियंत्रण में आर्थिक अपराध इकाई का गठन किया गया है, जिसका प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई को बनाया गया है।

2 राज्य में अर्थव्यवस्था में प्रगति होने के साथ-साथ आर्थिक अपराधों की शैली एवं स्वरूप में काफी परिवर्तन हुआ है। विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवंटित राशि में लगातार वृद्धि होने के कारण गबन एवं दुर्विनियोग के दृष्टांत भी अधिक संख्या में सामने आ रहे हैं। साथ ही, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में गबन/जाली नोटों तथा मादक पदार्थों की तस्करी भी गंभीर चिंता का विषय है। अतः आर्थिक अपराधों के अनुसंधानों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जिला पुलिस को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु आर्थिक अपराध इकाई में समय-समय पर पुलिस महानिरीक्षक स्तर से उपर स्तर के पदाधिकारी का पदस्थापन अपरिहार्य हो गया है।

3. अतएव आर्थिक अपराध इकाई के प्रभारी के रूप में अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई का एक गैर-संवर्गीय पद सृजित किये जाने की स्वीकृति दी जाती है ताकि आवश्यकतानुसार उक्त पद पर अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई अथवा पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई का पदस्थापन किया जा सके।

4. अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई के सृजित होने वाले गैर-संवर्गीय पद पर वार्षिक व्यय रु. 29,69,744/- (उन्तीस लाख उनहत्तर हजार सात सौ चौआलीस) रुपये सम्भावित है। यह व्यय मुख्य शीर्ष 2055-पुलिस उप मुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 101-आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता उपशीर्ष 0001 आपराधिक जांच विभाग पुलिस विपत्र कोड सं0-22-2055001010001 से किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई द्वारा की जायेगी।

5. आर्थिक अपराध इकाई के प्रभारी अपर पुलिस महानिदेशक होंगे तथा राज्य के आर्थिक अपराध से संबंधित किसी भी काण्ड का नियंत्रण किये जाने के संबंध में सक्षम पदाधिकारी के रूप में पूर्व से नामित प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई के स्थान पर अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई होंगे।

अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई एवं पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई दोनों के पदस्थापित रहने की स्थिति में अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई के प्रभारी होंगे तथा इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी रहेंगे। अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई के पदस्थापित नहीं रहने की स्थिति में पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई के प्रभारी होंगे तथा इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी रहेंगे।

6. इस संबंध में पूर्व में निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक-8752, दिनांक 01.12.2011 की कंडिकाएँ क्रमशः-3, 5 एवं 13 में निर्धारित प्रावधानों को उक्त हद तक संशोधित किया जाता है।

8. उपरोक्त प्रावधान दिनांक 01.01.2018 की तिथि से प्रभावी माने जायेंगे।

9. आर्थिक अपराध इकाई में अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई के एक गैर-संवर्गीय पद के सृजन के प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

10. प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
रंजन कुमार सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 347-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>